



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 26 जून, 2020/05 आषाढ़, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 मई, 2020

संख्या: रैव(डी0एम0सी0)-(बी0)1-(1)/2019 आर.एण्ड.पी.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राजस्व विभाग (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ), हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन प्रचालन केन्द्र

प्रभारी एवं प्रलेखन समन्वयक, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध - "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग, आपातकाल प्रचालन केन्द्र प्रभारी एवं प्रलेखन समन्वयक, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजस्व (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,  
ओंकार चन्द शर्मा,  
प्रधान सचिव (राजस्व)।

उपाबन्ध—"क"

हिमाचल प्रदेश राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग में आपातकाल प्रचालन केन्द्र प्रभारी एवं प्रलेखन समन्वयक, वर्ग-II (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—आपातकाल प्रचालन केन्द्र प्रभारी एवं प्रलेखन समन्वयक
2. **पद (पदों) की संख्या.**—12 (बारह)
3. **वर्गीकरण.**—वर्ग-II (अराजपत्रित)
4. **वेतनमान.**—(i) *नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान :* पे बैंड रुपए 10300—34800 /— जमा रुपए 5000 /— ग्रेड पे।

(ii) *संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां :* स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार रुपए 15300 /— प्रतिमास।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**—लागू नहीं

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—18 से 45 वर्ष:

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि उपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की

जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

**टिप्पणी.**—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

**7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं—**(क) *अनिवार्य अर्हता(ए)* : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपदा प्रबंधन/भूविज्ञान/भूगोल/पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।

या

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्थान या डीम्ड विश्वविद्यालय से आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(iii) सरकारी/पब्लिक सेक्टर उपक्रम (उपक्रमों) में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रलेखन और रिपोर्ट लिखने के कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

(ख) *वांछनीय अर्हता(ए)* : हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

**8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.**—*आयु* : लागू नहीं।

*शैक्षिक अर्हता* : लागू नहीं।

**9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:** *सीधी भर्ती/प्रोन्नति की दशा में* : (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनः नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

**10. भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—यथास्थिति, शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

**11. प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.**—लागू नहीं।

**12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.**—(क) *विभागीय प्रोन्नति समिति* : लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

**13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

**14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

**15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

**15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्वधीन की जाएगी:—

### (I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राजस्व, विभाग (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) में आपातकाल प्रचालन केन्द्र प्रभारी एवं प्रलेखन समन्वयक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/ नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में आना : सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

### (II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त आपातकाल प्रचालन केन्द्र प्रभारी एवं प्रलेखन समन्वयक को रुपए 15300/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रुपए 459/- (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

### (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :

सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

### (IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार

पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठक्रम आदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/ अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

#### (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

#### (VI) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-“ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

#### (VII) निबंधन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रुपए 15300/- प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष /वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 459/- रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति अधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जायेगा, तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ड) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

**16 आरक्षण.**—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

**17. विभागीय परीक्षा.**—लागू नहीं।

**18. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—ख

आपातकालीन प्रचालन केन्द्र प्रभारी एवं प्रलेखन समन्वयक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जानी वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति .....पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य सचिव, (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने आपातकालीन प्रचालन केन्द्र प्रभारी एवं प्रलेखन समन्वयक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार आपातकालीन प्रचालन केन्द्र प्रभारी एवं प्रलेखन समन्वयक के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ..... स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. "प्रथम पक्षकार" की संविदात्मक रकम रुपए 15,300/- प्रतिमास होगी।
3. "प्रथम पक्षकार" की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्त पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जायेगा, तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना

आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें परीक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)
2. ....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)
2. ....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर



*[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev(DMC)(B)1-1/2019/R&P dated 27-5-2020 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India].*

## REVENUE (DISASTER MANAGEMENT CELL) DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 27th May, 2020*

**No. Rev.(DMC)(B)1-1/2019.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Emergency Operation Centre Incharge-*cum*-Documentation Co-ordinator, Class-II (Non Gazetted) in the Department of Revenue (Disaster Management Cell), Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Revenue (Disaster Management Cell), Emergency Operation Centre Incharge-*cum*-Documentation Co-ordinator, Class-II (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh.

By order,

Onkar Chand Sharma,  
*Principal Secretary(Revenue).*

“Annexure-A”

### RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF EMERGENCY OPERATION CENTRE INCHARGE-CUM-DOCUMENTATION CO-ORDINATOR CLASS-II, (NON GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF REVENUE (DISASTER MANAGEMENT CELL) HIMACHAL PRADESH

**1. Name of the Post.**—Emergency Operation Centre Incharge-*cum*-Documentation Co-ordinator.

**2. Number of Post(Posts).**—12 (Twelve)

**3. Classification.**—Class-II (Non Gazetted)

**4. Scale of Pay.**—*Pay Scale for regular incumbents* : (i) Pay Band Rs. 10300-34800/- + Rs. 5000/- Grade Pay.

(ii) *Emoluments for Contract Employees* : Rs. 15,300/- P.M. as per details given in Column No.15-A.

**5. Whether “selection” post or non-selection post.**—Not applicable.

**6. Age for direct recruits.**—Between 18 years and 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government of H.P. including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Categories and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies.

**Note.**—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges or as the case may be.

**7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.**—(a) *Essential Qualification(s)* : (i) Master Degree in Disaster Management/Geology/Geography/Environmental Science from a recognised University.

OR

(ii) Post Graduate Diploma in Disaster Management from recognized University or from an Institution affiliated to a recognized University or from a deemed University.

(iii) A minimum of 03 (Three) years work experience in documentation and report writing in the field of disaster management in Government/Public Sector Undertakings(s).

(b) *Desirable qualification*: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

**8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).**—Age: Not applicable.

*Educational Qualification* : Not applicable

**9. Period of probation, if any.**—*Direct Recruitment* : (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after Superannuation and absorption.

**10. Method of recruitment— whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—**100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

**11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—**Not applicable.

**12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—**(a) *Departmental Promotion Committee* : “Not applicable”.

(b) *Departmental Confirmation Committee* : “As may be constituted by the Government from time to time”

**13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—**As required under the law.

**14. Essential requirement for a direct recruitment.—**A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

**15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—**Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test(objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

**15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment.—**Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

### **(I) CONCEPT:**

(a) Under this policy, the Emergency Operation Centre Incharge-cum-Documentation Co-ordinator in the Department of Revenue (Disaster Management Cell) Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for further extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory based on his/her performance during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

(b) *POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC* : The Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government for fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

### **(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:**

The Emergency Operation Centre Incharge-cum-Documentation Co-ordinator appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 15,300/- P.M. (which shall

be equal to minimum of the Pay Band + Garde Pay). An amount of Rs. 459/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

### **(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:**

The Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

### **(IV) SELECTION PROCESS:**

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test(objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

### **(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:**

As may be constituted by the concerned recruiting agency/authority *i.e* Himachal Pradesh, Public Service Commission.

### **(VI) AGREEMENT:**

After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-‘B’ appended to these Rules.

### **(VII) TERMS AND CONDITIONS:**

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 15,300/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount Rs. 459/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) as annual increase of the post for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorised Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorised absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorised absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the Controlling Authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF / GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

**16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

**17. Departmental Examination.**—Not Applicable

**18. Powers to relax.**—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C., relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE EMERGENCY OPERATION CENTRE INCHARGE-CUM-DOCUMENTATION CO-ORDINATOR AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH THE SECRETARY(REVENUE) TO THE GOVERNMENT OF H.P.

This agreement is made on this.....day of.....in the year .....between Sh./Smt..... s/o/d/o ..... r/o ..... contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor, Himachal Pradesh through Secretary(Rev) to the Government of Himachal Pradesh (hereinafter called the "SECOND PARTY").

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Emergency Operation Centre Incharge-cum-Docummentation Co-ordinator on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Emergency Operation Centre Incharg-cum-Docummentation Co-ordinator for a period of one year commencing on day of.....and ending on the day of .....It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on .....and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/ renewal of contract period on year to year basis, concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended:

2. The Contractual amount of the First Party will be Rs. 15300/- per month.
3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
4. Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorised Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/CPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES :

1. ....

(Name and full address )

Signature of the FIRST PARTY

2. ....

(Name and full address )

Signature of the SECOND PARTY

## राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 19 मार्च, 2020

**संख्या: रैव(डी0एम0सी0)-(बी0)1-(1)/2019 आर.एण्ड.पी.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राजस्व विभाग (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ), हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजस्व (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
(ओंकार चन्द शर्मा),  
प्रधान सचिव (राजस्व)।

उपाबन्ध-“क”

हिमाचल प्रदेश राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**— सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ
2. **पद (पदों) की संख्या:** 1 (एक)
3. **वर्गीकरण:** वर्ग-II (अराजपत्रित)
4. **वेतनमान.**—(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान : पे बैंड ₹ 10300-34800 /— जमा ₹ 5000 /— ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) लिए उपलब्धियों: स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्योरे के अनुसार ₹ 15300 /— प्रतिमास।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**—लागू नहीं

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—18 से 45 वर्ष:

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :



परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

**टिप्पणी.**—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

**7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.**—(क) *अनिवार्य अर्हता(एं)* : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सहबद्ध संस्थान से या डीम्ड विश्वविद्यालय से एम.सी.ए. या सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में बी.ई./बी.टैक की उपाधि।

या

डी.ओ.ई.ए.सी.सी. (डोएक)/एन.आई.ई.एल.आई.टी. (नाइलिट) सोसाइटी से बी स्तर का कोर्स।

(ii) सरकारी/पब्लिक सेक्टर संगठन में सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित गतिविधियों में वैबपोर्टल प्रबंधन, एम.आई.एस/डाटा बेस प्रबंधन में कम से कम 3 (तीन) वर्ष का कार्य करने का अनुभव।

(ख) *वांछनीय अर्हता(एं)* : हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

**8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.**—*आयु* : लागू नहीं।

*शैक्षिक अर्हता* : लागू नहीं।

**9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परीक्षा नहीं होगी।

**10. भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.**—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैक्रेण्डमैट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैक्रेण्डमैट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—हिमाचल सरकार के अन्य विभागों/बोर्डों/निगमों में इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैक्रेण्डमैट के आधार पर।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी:—

#### (I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

#### (II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को ₹ 15300/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्पूर्वी वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 459/- (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

**(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :**

सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

**(IV) चयन प्रक्रिया :**

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

**(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :**

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

**(VI) करार :**

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-“ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

**(VII) निबंधन और शर्तें :**

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 15300/- प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 459/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगा संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जायेगा, तथापि आपवधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

**16. आरक्षण.**—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

**17. विभागीय परीक्षा.**—लागू नहीं।

**18. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जानी वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति .....पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ..... स्वयंमव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 15,300/- प्रतिमास होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्ति महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जायेगा, तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा।

तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें परीक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

2. ....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)
2. ....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

*[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev(DMC)(B)1-1/2019/R&P dated 19-3-2020 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India].*

## REVENUE (DISASTER MANAGEMENT CELL) DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla –171002, the 19th March, 2020*

**No. Rev.(DMC)(B)1-1/2019/R&P.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of “Information Technology Specialist”, Class-II (Non Gazetted) in the Department of Revenue (Disaster Management Cell), Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Revenue (Disaster Management Cell), Information Technology Specialist, (Class-II Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh.

By order,

Onkar Chand Sharma,  
*Principal Secretary(Revenue).*

“Annexure-A”

### RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST, CLASS-II (NON GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF REVENUE (DISASTER MANAGEMENT CELL) HIMACHAL PRADESH

- 1. Name of the Post.**—Information Technology Specialist
- 2. Number of Post(s).**—1 (One)
- 3. Classification.**—Class-II (Non Gazetted)
- 4. Scale of Pay : Pay band for regular incumbents.**—(i) Pay band Rs. 10300-34800/- + Rs. 5000/- Grade Pay  
(ii) *Emoluments for Contract Employees* : Rs. 15300/- P.M. as per details given in Column No.15-A.
- 5. Whether “selection” post or “Non-selection” post.**—Not applicable.
- 6. Age for direct recruitment.**—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government of H.P. including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies.

**Note.**—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges or as the case may be.

**7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).**—(a) *Essential Qualification(s)* : (i) MCA or B.E / B. Tech. Degree in IT / Computer Science from any recognized University or an Institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University.

OR

“B” level course from DOEACC/NIELIT Society.

(ii) A minimum of 3 years work experience in IT related activities, management of web portal, MIS/Database Management in Government or Public Sector Organization.

(b) *Desirable Qualification(s)* : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

**8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote (s).**—*Age*: Not applicable

*Educational Qualification(s)* : Not applicable

**9. Period of probation, if any.**—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

**10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.**—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.



**11. In case of recruitment by promotion/secondment / transfer (grade(s) from which promotion/secondment/transfer) is to be made.**—On secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other HP Government Departments/Boards/ Corporations.

**12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**—(a) *Departmental Promotion Committee* : “Not applicable”

(b) *Departmental Confirmation Committee* : “As may be constituted by the Government from time to time”

**13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**—As required under the law.

**14. Essential requirement for a direct recruitment.**—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

**15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.**—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test(objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

**15-A. Selection for appointment to the post by Contract appointment.**—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

#### (I) CONCEPT:

(a) Under this policy, the Information Technology Specialist in the Department of Revenue, Disaster Management Cell, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/ extended.

(b) *POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC* : The Secretary(Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

#### (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Information Technology Specialist appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 15300/- P.M. (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay). An amount of Rs. 459/- (3% of the minimum of the pay band+grade

pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year will be allowed if contract is extended beyond one year.

### **(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:**

The Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.

### **(IV) SELECTION PROCESS:**

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test(objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

### **(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:**

As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Public Service Commission.

### **(VI) AGREEMENT:**

After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-‘B’ appended to these Rules.

### **(VII) TERMS AND CONDITIONS:**

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 15,300/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 459/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him /her.

(c) The Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorised Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorised absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorised absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the Controlling Authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

**16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

**17. Departmental Examination.**—Not Applicable

**18. Powers to relax.**—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE –"B"

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

THROUGH THE SECRETARY (REVENUE) TO THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

This agreement is made on this.....day of.....in the year.....between Sh./Smt..... s/o/d/o ..... r/o ..... contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor, Himachal Pradesh through the Secretary(Revenue) to the Government of Himachal Pradesh (hereinafter called the "SECOND PARTY").

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Information Technology Specialist on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Information Technology Specialist for a period of one year commencing on day of .....and ending on the day of .....It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on .....and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/ renewal of contract period on year to year basis, concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended:

2. The Contractual amount of the First Party will be Rs.15300/- per month.
3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him /her.
4. Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorised Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond

his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES :

1. ....  
 .....  
 (Name and full address)

Signature of the FIRST PARTY

2. ....  
 .....  
 (Name and full address)

Signature of the SECOND PARTY

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 :  
07/2020

तारीख रजुआ :  
17-06-2020

तारीख फैसला :

Sh. Gian Prakash s/o Late Sh. Sonam Bar, r/o Village & P.O. Kalpa, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur (H. P.).

**बनाम**

1. आम जनता ग्राम कल्पा
2. प्रधान ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

विषय.—प्रार्थी के भाई बीरबल सिंह की मृत्यु ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Gian Prakash ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके भाई बीरबल सिंह की मृत्यु दिनांक 10-07-2001 को गांव कल्पा में हुई है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस विषय में आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Gian Prakash के भाई स्व0 श्री बीरबल सिंह की मृत्यु दिनांक 10-07-2001 को हुई है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-07-2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव ग्राम पंचायत कल्पा को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 17-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)**

नं0 मुकद्दमा : 49/2019

तारीख दायर : 26-12-2019

श्री मदन लाल पुत्र श्री मस्त राम, गांव व डाकघर मुनीश बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

**बनाम**

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त (नाम दुरुस्ती)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्री मदन लाल पुत्र श्री मस्त राम, गांव व डाकघर मुनीश बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में मदन लाल दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल मुनिश के कागजात माल में वादी का नाम मधु दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल मुनिश के कागजात माल में अपना नाम मधु के स्थान पर मदन लाल दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 13-07-2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 12-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 64/2018

तारीख दायर : 31-07-2018

श्री नरैण दास पुत्र श्री करासी, गांव पटेना, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त (नाम दुरुस्ती)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्री नरैण दास पुत्र श्री करासी, गांव पटेना, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड व मतदाता पहचान-पत्र में नरैण दास दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल बाहली व कुहल पटेना के कागजात माल में वादी का नाम नेऊ दर्शाया गया है जो सही नहीं है वादी महाल बाहली व कुहल पटेना के माल कागजात में अपना नाम नेऊ के स्थान पर नरैण दास दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 13-07-2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी

उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 12-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 04 / 2020

तारीख दायर : 22-01-2020

श्री कुशल चन्द पुत्र श्री मेघा नन्द, निवासी गांव मझाली, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त (नाम दुरुस्ती)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्री कुशल चन्द पुत्र श्री मेघा नन्द, निवासी गांव मझाली, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, विद्यालय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र व पैन कार्ड में कुशल चन्द दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल मझाली, देवठी व चिकसा के कागजात माल में वादी का नाम बिट्टू दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल मझाली, देवठी व चिकसा के कागजात माल में अपना नाम बिट्टू के स्थान पर कुशल चन्द दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 13-07-2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 12-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।



**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)**

नं0 मुकद्दमा : 12/2019

तारीख दायर : 29-04-2019

श्री बीरबल पुत्र श्री हीरावीर, निवासी गांव दरकाली, डाकघर दरकाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त (नाम दुरुस्ती)।।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्री बीरबल पुत्र श्री हीरावीर, निवासी गांव दरकाली, डाकघर दरकाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में बीरबल दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल दरकाली के कागजात माल में वादी का नाम जिया लाल दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल दरकाली के कागजात माल में अपना नाम जिया लाल के स्थान पर बीरबल दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 13-07-2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 12-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)**

नं0 मुकद्दमा : 24/2019

तारीख दायर : 25-02-2019

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री ज्ञान सिंह, निवासी पटेना, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त.—(नाम दुरुस्ती)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री ज्ञान सिंह, निवासी गांव पटेना, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व विद्यालय प्रमाण-पत्र में सुनीता देवी दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल बाहली व कुहल पटेना के कागजात माल में वादी का नाम नीतू दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल बाहली व कुहल पटेना के कागजात माल में अपना नाम नीतू के स्थान पर सुनीता देवी दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 13-07-2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 12-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 30/2019

तारीख दायर : 12-07-2019

श्री हिमेश पुत्र श्री बंसी लाल, निवासी विजय भवन, शीश महल, वार्ड नं0 1, रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त (नाम दुरुस्ती)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्री हिमेश पुत्र श्री बंशी लाल, निवासी विजय भवन, शीश महल, वार्ड नं0 1, रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड व पैन कार्ड में हिमेश ठाकुर दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल नेहरा के कागजात माल में वादी का नाम हिम्मत सिंह दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल नेहरा के कागजात माल में अपना नाम हिम्मत सिंह के स्थान पर हिमेश दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 13-07-2020 को या

इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 12-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

### ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

प्रार्थना-पत्र श्री कौर सिंह पुत्र श्री झेखरू, निवासी ग्राम खुड़वी, डाकघर रुसलाह, तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, ग्राम पंचायत पुजारली के परिवार रजिस्टर में नाम की दुरुस्ती करने बारे।

ग्राम पंचायत पुजारली

बनाम

आम जनता

श्री कौर सिंह पुत्र श्री झेखरू, निवासी ग्राम खुड़वी, डाकघर रुसलाह, तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत पुजारली के परिवार रजिस्टर में कौर लिखा गया है जबकि उसका सही नाम कौर सिंह है, पुष्टि हेतु शपथ-पत्र आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड की छाया प्रति व नकल परिवार रजिस्टर संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि ग्राम पंचायत पुजारली के परिवार रजिस्टर में उसका नाम कौर के स्थान पर कौर सिंह दुरुस्त किया जाए।

अतः हर आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम या खास को प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 07-07-2020 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो प्रस्तुत करे। दिगर सूरत में दिनांक 07-07-2020 को ग्राम पंचायत पुजारली के परिवार रजिस्टर में श्री कौर पुत्र श्री झेखरू के स्थान पर श्री कौर सिंह पुत्र श्री झेखरू के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 08-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव,  
जिला शिमला (हि0 प्र0)**

सुरजमणि

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती सुरजमणि पुत्री स्व0 श्री शिवानंद, निवासी गांव दिउची, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने दरखास्त गुजारी है कि वह अपने पिता स्व0 श्री शिवानंद की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरशाली के रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का कहना है कि वह किसी कारणवश अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरशाली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवा सकी। प्रार्थिया के पिता की मृत्यु की तिथि 17-06-1984 है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को इस बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन मिति 08-07-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा और उक्त प्रार्थिया के पिता की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरशाली के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

-----

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव,  
जिला शिमला (हि0 प्र0)**

श्री बनीत कुमार

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री बनीत कुमार पुत्र हिरा नंद निवासी गांव ग्यारी, डाकघर कान्थली, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है कि वह अपने पुत्र अभि के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत धगोली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का कहना है कि वह किसी कारणवश अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण उक्त पंचायत के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। प्रार्थी के पुत्र अभि की जन्म तिथि 28-12-2015 है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन मिति 02-07-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज/दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और नियमानुसार प्रार्थी के पुत्र के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत धगोली के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

Sh. Surta Ram पुत्र श्री Chhajju Ram, निवासी Palhori, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Surta Ram पुत्र श्री Chhajju Ram, निवासी Palhori, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री Luxmi Devi की जन्म तिथि 01-01-1984 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Palhori में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 01-01-1984 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Luxmi Devi की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Palhori, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 08-07-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Luxmi Devi की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

**ब अदालत श्री जय राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

दुला राम पुत्र प्रितम, ग्राम सिधोटी, उप—तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

दुला राम पुत्र श्री प्रितम, ग्राम निवासी सिधोटी, डाकघर पनोग, उप—तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी/दस्तावेजात सहित एक प्रार्थना—पत्र दिया है कि प्रार्थी के पिता का हकीकी नाम प्रितम है, जोकि ग्राम पंचायत पनोग व आवश्यक दस्तावेजात में भी दर्ज है। जबकि राजस्व अभिलेख बाका मौजा पनोग में रामिया दर्ज है। जिससे प्रार्थी को असुविधा हो रही है। प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख में प्रितम करवाना चाहता है।

अतः इस बारे आम जनता को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को अगर इस बारा कोई उजर/आपत्ति/एतराज हो तो वह दिनांक 03-07-2020 तक लिखित रूप में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा, तथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील रोन्हाट,  
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।